

छह साल में पांच गुना बढ़ गई प्रदेश में ग्रीन एनर्जी

परीक्षित निर्भय

अलीगढ़। छह साल में ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में बड़ी छलांग लगाते हुए क्षमता में करीब पांच गुना बढ़ोतरी की है। आगरा, अयोध्या, अमेठी, औरैया और बदायूं सहित 30 जिलों में 1979 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित हुई है। हालांकि जिलेवार स्थिति देखें तो कहीं सोलर प्लांट तेजी से लग रहे हैं, तो कई जिले अब भी इंतजार में हैं। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) के आंकड़े बताते हैं कि 2020-21 से 2025-26 के बीच प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की क्षमता 415 से बढ़कर 1979 तक पहुंची है, लेकिन लखनऊ, अलीगढ़ समेत करीब 45 जिले ऐसे हैं, जहां अब तक कोई बड़ा सोलर प्रोजेक्ट शुरू

जमीन, निवेश और प्रशासनिक पहल का असर : लखनऊ, अलीगढ़, मथुरा, शामली, बागपत, कासगंज जैसे जिले अब भी यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं से वंचित हैं। ऊर्जा विशेषज्ञ विनीत दास का मानना है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति-2022, जैव ऊर्जा नीति-2022 और हरित हाइड्रोजन नीति-2024 लागू हैं। जिन जिलों में जमीन की उपलब्धता, निवेश और प्रशासनिक पहल बेहतर रही, वहां प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ गए। सभी जिलों में समान रूप से फोकस करें तो ग्रीन एनर्जी उत्पादन में सबसे आगे हो सकता है।



इन जिलों में जैव ऊर्जा हुई मजबूत : कृषि अवशेष और कचरे की उपलब्धता को देखते हुए 28 जिलों में कुल 867.63 टीपीडी/केएलपीडी क्षमता के बायो-कोल, बायोडीजल और कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, हापुड, उन्नाव, मेरठ व लखनऊ में बायो डीजल और बहराइच, बरेली, बुलंदशहर, इटावा, हरदोई, देवरिया और हमीरपुर जिला बायो-कोल क्षमता में सबसे आगे है। बलरामपुर, बाराबंकी, बदायूं, फरीदपुर, गोरखपुर, कन्नौज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर और वाराणसी में कंप्रेस्ड बायोगैस की क्षमता विकसित हुई है।

नहीं हो सका। राज्य सरकार की ओर से सोलर, बायो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की गई हैं। इसका परिणाम है कि जालौन सर्वाधिक 247 मेगावाट क्षमता युक्त सौर परियोजनाओं के साथ प्रदेश का

सोलर हब बन गया है, जबकि झांसी और कानपुर नगर जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ये तीनों जिले मिलकर 654 मेगावाट ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं जो राज्य की कुल सोलर उत्पादन क्षमता का करीब एक तिहाई

हिस्सा है। इसके उलट कई बड़े और विकसित माने जाने वाले जिले इस दौड़ में पीछे हैं। पश्चिमी यूपी के मेरठ में पिछले चार साल से कोई नया सोलर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है, जबकि आगरा में भी पिछले दो वर्षों से इस दिशा में कोई नई पहल नहीं दिखी है।

सौर ऊर्जा से लैस सरकारी भवन प्रदेश के सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की पहल में राजधानी लखनऊ के अलावा गौतमबुद्ध नगर, प्रयागराज और मेरठ जिले ने बाजी मारी है। यहाँ भवनों की छतों पर क्रमशः 10124, 5623, 4819 और 3443 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पैनल लगा चुके हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि कासगंज, शामली, बागपत, हाथरस और श्रावस्ती जैसे जिलों में यह पहल अब भी बेहद सीमित है।

सोलर परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके फायदे का आकलन किया जाता है। प्रदेश में खेती योग्य जमीन को भी बचाना है। जहां खेती से अनुपयोगी जमीन ज्यादा है, वहां सोलर को परियोजनाएं लगाई जा रही हैं। बुंदेलखंड में सूर्य की किरणों सीधे पड़ती हैं। इंद्रजीत सिंह, निदेशक यूपीनेडा

